

Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP,
Ludhiana, Shimla,
Bihar, Jammu, Jaipur
Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)



NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779



Fri 04 Sep - 2026

Year - 01

Issue - 161

Page - 01

Rs. - 5

www.azadvaani.com

रिपोर्टर मुस्लिम है तो क्या पुलिस उसे पीटेगी?

दिल्ली पुलिस द्वारा मुस्लिम महिला पत्रकार से कथित दुर्व्यवहार और मारपीट, पत्रकारों ने जताया कड़ा विरोध



साकेत पुलिस स्टेशन में मुस्लिम पत्रकारों के साथ कथित मारपीट का गंभीर आरोप, महिला पत्रकार शाहीन खान ने लगाया पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप; दावा—रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें जबरन थाने ले जाकर कमरे में रखा गया, महिला पुलिसकर्मी ने डंडों और थप्पड़ों से पीटा और फोन छीन लिया, वहीं भाई के फोन करने पर उनके नाम में 'खान' देखकर कथित तौर पर और भी ज्यादा बेरहमी से मारपीट की गई; पत्रकारों ने कार्रवाई और न्याय की मांग उठाई

पंजाब में 181 शिक्षकों को हेडमास्टर पद पर पदोन्नति, स्कूलों में मजबूत होगा नेतृत्व



चंडीगढ़, 4 सितंबर: पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से 181 शिक्षकों को हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया है। इसके साथ ही 4 ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारियों को भी पदोन्नति दी गई है। सरकार का मानना है कि इन पदों को भरने से स्कूलों में जमीनी स्तर पर नेतृत्व मजबूत होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि ये पदोन्नतियां शिक्षकों के पेशेवर विकास और करियर में उन्नति का महत्वपूर्ण अवसर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के हितों और उनके पेशेवर विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पदोन्नत किए गए 181 शिक्षकों में 140 सामान्य वर्ग से संबंधित हैं, जबकि 23 शिक्षक अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। इसके अलावा 6 दिव्यांग श्रेणी और 8 बैकलॉग पीडब्ल्यूडी कोटे के शिक्षकों को भी हेडमास्टर पद पर पदोन्नति दी गई है। वहीं, 4 ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारियों को भी पदोन्नति का लाभ मिला है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में प्रभावी नेतृत्व विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति के साथ-साथ शिक्षकों के बेहतर मार्गदर्शन के लिए भी आवश्यक है। नए हेडमास्टर स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करने और विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

हरजोत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक सरकारी स्कूल को सक्षम और जिम्मेदार नेतृत्व उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा हेडमास्टर केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां नहीं निभाता, बल्कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रेरित कर स्कूल के समग्र विकास में नेतृत्व प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि पदोन्नति की प्रक्रिया वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। सरकार ने योग्य उम्मीदवारों को उनकी पात्रता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अवसर देने का प्रयास किया है, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे।

शिक्षा मंत्री ने पदोन्नत होने वाले सभी शिक्षकों और अधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली को मजबूत करने में हेडमास्टरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। सरकार के अनुसार, नए हेडमास्टरों की नियुक्ति से स्कूलों में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद मिलेगी।

जन्माष्टमी पर पंजाब के 85 हजार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA 42% से बढ़ाकर 60% करने की सिफारिश



चंडीगढ़, 4 सितंबर 2026: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों को जन्माष्टमी का बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए उन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की सिफारिश की है, जिनका वेतन केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के पैटर्न पर निर्धारित है। अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दी जाएगी।

इस संबंध में तीन सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी ने फैसला लिया है। कमेटी में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर शामिल हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी।

अमन अरोड़ा ने कहा कि कर्मचारी सुशासन की रीढ़ हैं और सरकार उनके अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पोस्ट-2020 भर्ती वाले कर्मचारियों को केंद्रीय 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन ढांचे में लाया गया, लेकिन उन्हें अभी तक 42 प्रतिशत DA मिल रहा था। ऐसे में केंद्र के समान 60 प्रतिशत DA देने की आवश्यकता महसूस हुई।

उन्होंने बताया कि 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती कर्मचारी पंजाब की ऐतिहासिक रूप से बेहतर वेतन संरचना का लाभ उठा रहे हैं, जबकि बाद में भर्ती कर्मचारियों का शुरुआती वेतन केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप है। इसलिए कम DA का अंतर इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

सरकार के अनुसार, इस निर्णय से करीब 85 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें 20,603 शिक्षक, 11,685 कांस्टेबल, 5,144 क्लर्क, 2,355 नर्स, 2,267 चपरासी, 1,467 मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर, 1,248

मेडिकल ऑफिसर, 1,214 पटवारी और 1,129 जूनियर पैदा हो गया था।

अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब का कोई भी कर्मचारी अपने केंद्रीय समकक्ष से कम वेतन न ले। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वेतन समानता की बात की जा रही है तो उन्हें पहले अपने-अपने राज्यों में भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते सुनिश्चित करने चाहिए।

सरकार ने इसे कर्मचारियों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे पोस्ट-2020 कर्मचारियों की वेतन संबंधी असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी।

सरकार के इस फैसले को पोस्ट-2020 भर्ती कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी असमानता को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। DA में बढ़ोतरी से इन कर्मचारियों की मासिक आय में सीधे तौर पर इजाफा होगा और उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के समान DA दर का लाभ मिल सकेगा।

कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिश ऐसे समय में सामने आई है जब पोस्ट-2020 कर्मचारियों के DA को लेकर राज्य में लगातार चर्चा चल रही थी। कर्मचारियों की ओर से भी यह मांग उठाई जाती रही है कि जब उनका वेतन ढांचा केंद्रीय 7वें वेतन आयोग के अनुरूप है, तो DA की दर भी केंद्रीय स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।

सरकार के अनुसार, 17 जुलाई 2020 के बाद हुई भर्तियों के लिए वेतन ढांचे में बदलाव का उद्देश्य राज्य में नई नियुक्तियों को संशोधित वेतन प्रणाली के अनुरूप लाना था। हालांकि, DA की अलग दर बने रहने के कारण इस वर्ग के कर्मचारियों में वेतन और भत्तों को लेकर अंतर

इस फैसले का असर शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व और तकनीकी विभागों समेत कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर पड़ेगा। बड़ी संख्या में युवा कर्मचारी इन विभागों में हाल के वर्षों में भर्ती हुए हैं, जिससे यह निर्णय पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित 60 प्रतिशत DA का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कर्मचारी जिनके वेतन या सेवा संबंधी मामले न्यायालय के आदेशों के तहत अलग तरीके से निर्धारित हैं, उन्हें इस निर्णय के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित 60 प्रतिशत DA का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कर्मचारी जिनके वेतन या सेवा संबंधी मामले न्यायालय के आदेशों के तहत अलग तरीके से निर्धारित हैं, उन्हें इस निर्णय के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

DA बढ़ाने की सिफारिश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे पोस्ट-2020 कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच DA दर का अंतर कम होगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों में वेतन संबंधी असंतोष कम करने और प्रशासनिक व्यवस्था में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिलेगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि कर्मचारियों की सेवाओं और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से चलाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके हितों को ध्यान में रखकर लिए गए फैसले सीधे तौर पर सरकारी कामकाज की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

शिक्षक दिवस पर 75 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार देगी मान सरकार

चंडीगढ़, 4 सितंबर: पंजाब सरकार शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 75 शिक्षकों को प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026 से सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में शिक्षकों की भूमिका को मान्यता देते हुए यह फैसला लिया है।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने बताया कि पुरस्कारों के लिए सभी शिक्षकों का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति के तहत पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया से किया गया है। सरकार ने चयन में उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को प्रमुख आधार बनाया है।

उन्होंने बताया कि चयनित 75 शिक्षकों में 55 को राज्य शिक्षक पुरस्कार, 10 को यंग शिक्षक पुरस्कार, 4 को विशेष शिक्षक पुरस्कार और 6 को प्रबंधकीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना और उन्हें आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का ज्ञान देने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे बच्चों के सपनों को दिशा देने और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिक्षकों की मेहनत और समर्पण से ही स्कूलों में सकारात्मक बदलाव संभव होता है।

हरजोत सिंह बैस ने कहा कि सरकार शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने को अपना महत्वपूर्ण दायित्व मानती है। उन्होंने कहा कि पुरस्कारों की पारदर्शी चयन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सम्मान के लिए केवल उत्कृष्टता, मेहनत और समर्पण को प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्कूल शिक्षा में उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक शिक्षक को बेहतर कार्य करने के लिए उचित मंच और सम्मान मिले।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में हाल के वर्षों में हुए सकारात्मक बदलावों का श्रेय शिक्षकों की मेहनत और प्रतिबद्धता को जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक लगातार नई शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

बैस ने बताया कि नीति आयोग द्वारा पंजाब को 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा के परिणामों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण-2024 में भी पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि पंजाब की सरकारी स्कूल शिक्षा में हो रहे निरंतर सुधार और शिक्षकों की अथक मेहनत को दर्शाती है।

हरजोत सिंह बैस ने पुरस्कारों के लिए चयनित सभी 75 शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनका समर्पण दूसरे शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। उन्होंने समूचे शिक्षक वर्ग से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की अपील की।



पंजाब में 36 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ



चंडीगढ़, 4 सितंबर: पंजाब सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्य के 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत अब तक 2,697.44 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि डीबीटी व्यवस्था ने वित्तीय सहायता के वितरण को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है तथा बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया है।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान में पंजाब के 36 लाख से अधिक नागरिक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी सहायता के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि के माध्यम से वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, आश्रित बच्चों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भरोसा और सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है, जहां प्रत्येक पात्र नागरिक को समान अवसर और समय पर सरकारी सहायता मिल सके।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र लाभार्थी को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से पात्र लोगों की सक्रिय रूप से पहचान करने और उनके मामलों का निर्धारित समय के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता बनाए रखने के निर्देश भी दिए।



SquareNet
Innovation & Excellence



Advertisement



Zoho Mail



Google Workspace



Microsoft 365



Microsoft Solutions Partner



Google Cloud Partner



aws partner network

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**



Secure & Reliable



Professional Email



Cloud Integration



24/7 Expert Support



Scalable for Every Business



SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India



www.squarenetindia.com



mail@squarenetsolutions.com



+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: **+91-90414-88440**

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015